पी. बालकोतैया

बनाम

भारत संघ और अन्य

(और संबंधित अपीलें)

(एस.आर. दास, सी.जे., वेंकटरामा अय्यर, एस.के. दास, ए.के.

सरकार और विवियन बॉस जेजे.)

रेलवे सेवाएँ-राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा के लिए नियम-संवैधानिकता-विध्वंसक गतिविधि में लगे कर्मचारी-सेवाओं की समाप्ति (राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा) नियम, 1949 आर. 3,7, - भारत का संविधान, अनुच्छेद 14, 19 (1) (सी), 311।

अपीलार्थियों की सेवाएं जो रेलवे सेवक थे, उन्हें रेलवे सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा) नियम, 1949 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से समाप्त कर दिया गया था। उस धारा के तहत कारण बताने के लिए उन पर निम्नलिखित नोटिस जारी किए गए:

"जबकि महाप्रबंधक की राय में, आपको बी.एन. रेलवे कर्मचारी संघ (कम्युनिस्ट प्रायोजित) का सदस्य और कार्यालय सचिव होने का संदेह है और आप ओम प्रकाश मेहता, बी. एन. मुखर्जी, आर. एल. रेड्डी आदि जैसे कम्युनिस्टों के साथ इस तरह से जुड़े हुए थे कि राज्य के प्रति आपकी विश्वसनीयता और निष्ठा के बारे में संदेह पैदा हो कि भले ही आप एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन आपने कम्युनिस्टों की निजी बैठकों में भाग लिया, नवंबर 1948 से जनवरी 1949 तक आम हड़ताल के लिए रेलवे कर्मचारियों के बीच आंदोलन किया, जिससे संचार और आवश्यक आपूर्ति की आवाजाही

बाधित हो गई और जिससे देश में अव्यवस्था और भ्रम पैदा हुआ और इसके परिणामस्वरूप आप उक्त नियम 3 के तहत अपनी सेवाओं को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उन पर निलंबन के आदेश पारित किए गए। उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया। जांच पर सलाहकारों की समिति और उनकी जांच के बाद पाया गया कि आरोप सही थे और इसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करने वाले महाप्रबंधक ने अपीलार्थियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया, उन्हें नोटिस के बदले एक महीने का वेतन दिया। अपीलकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि सुरक्षा नियम संविधान के अनुच्छेद 14,19 (जे) (सी) और 311 का उल्लंघन करते हैं और इस तरह उनकी सेवाओं को समाप्त करने वाले आदेश अमान्य हैं। उच्च न्यायालय ने सुरक्षा नियमों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय नहीं लिया और अन्य आधारों पर याचिकाओं को खारिज कर दिया।"

यह अभिनिर्धारित किया गया कि रेलवे सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा) नियम, 1949 के नियम 3 में होने वाली 'विध्वंसक गतिविधियाँ' शब्द, राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में, जो उनके विचार में है, एक वैध वर्गीकरण को बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से सटीक है और इसलिए नियम संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल होने के रूप में अमान्य नहीं हैं।

अनंतनारायणन बनाम दक्षिणी रेलवे, ए.आई. र. 1956 मैड. 220, अस्वीकृत।

आरोप से पता चलता है कि अपीलार्थियों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की गई थी कि वे कम्युनिस्ट या ट्रेड यूनियनवादी थे, बल्कि इसलिए की गई थी कि वे विध्वंसक गतिविधियों में लगे हुए थे। इसलिए उनकी सेवाओं को समाप्त करने वाले आदेश संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) का उल्लंघन नहीं कर सकते थे क्योंकि

उन्होंने उस अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत अपीलार्थियों के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया था जो ठीक वैसा ही रहा जैसा वे पहले थे।

संविधान का अनुच्छेद 311 केवल तभी लागू हो सकता है जब बर्खास्तगी या सजा के माध्यम से हटाने का आदेश हो। चूंकि अपीलार्थियों के रोजगार की शर्तों में यह प्रावधान था कि उनकी सेवाओं को एक उचित सूचना पर समाप्त किया जा सकता है और सुरक्षा नियमों की धारा 7 ने पेंशन, उपदान और सेवा नियमों के तहत एक कर्मचारी के हकदार होने जैसे अधिकारों को संरक्षित किया है, इसलिए न तो समय से पहले समाप्ति हुई थी और न ही पहले से प्राप्त लाभों को जब्त किया गया था ताकि सजा हो सके। सुरक्षा नियमों की धारा 3 के तहत सेवाओं को समाप्त करने का आदेश रेलवे प्रतिष्ठान संहिता की धारा 148 के तहत निर्वहन के आदेश के समान था और संविधान के अनुच्छेद 311 के अर्थ के भीतर न तो बर्खास्तगी का था और न ही हटाने का। इसलिए अनुच्छेद 311 का कोई उपयोग नहीं था।

परशोतम लाल ढींगरा बनाम भारत संघ 1957 की सिविल अपील सं. 65 पर भरोसा किया गया।

सतीश चंद्र आनंद बनाम भारत संघ, [1953] एससीआर 655, श्याम लाट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और भारत संघ, [1955] 1 एससीआर 26 और बॉम्बे राज्य बनाम सौभाग्यचंद एम. दोशी, 1955 की सिविल अपील संख्या 182, का उल्लेख किया गया है।

यद्यपि नियम स्पष्ट रूप से संभावित हैं, लेकिन इसके तहत किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सामग्री नियमों के अधिनियमन से पहले उसके आचरण से ली जा सकती है।

रानी बनाम सेंट मैरी, व्हाइटचैपल, (1848) 12 क्यू. बी. 120 और रानी बनाम क्राइस्टचर्च, [1848] 12 क्यू. बी. 149 का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील संख्या 46-48/1956।

1951 की विविध याचिका संख्या 45, 1568 और 1569 में पूर्व नागपुर उच्च न्यायालय के 16 नवंबर, 1951 के निर्णय और आदेश से अपील।

सी.ए. संख्या 46 और 56 के 47 में अपीलार्थियों के लिए एच.जे. उमरीगर, डी. एल. जयवंत और नौनीत लाल।

डी.एल. जयवंत और नौनीत लाल, सी.ए. संख्या 56 के 48 में अपीलार्थी के लिए।

प्रत्यर्थी की ओर से आर. गणपति अय्यर और आर.एच. ढेबर (सभी अपीलों में)।

3 दिसंबर 1957।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय इनके द्वारा दिया गया था।

वेंकटरामा अय्यर जे.-

अपीलों को नागपुर उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ निर्देशित किया जाता है, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है, और क्योंकि वे एक ही तथ्यों से उत्पन्न होते हैं और निर्धारण के लिए एक ही बिंदु उठाते हैं, उन्हें एक साथ सुना गया था, और एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जाएगा।

1956 के सिविल अपील संख्या 46 में तथ्य-संबंधित अपीलों में तथ्य समान हैं और यह बताने की आवश्यकता नहीं है-यह है कि अपीलार्थी 1939 में बंगाल नागपुर

रेलवे में नागपुर में कार्यशाला में क्लर्क के रूप में कार्यरत था। 1946 में जब राज्य ने रेलवे का प्रशासन संभाला, तो उसने कर्मचारियों को 5 जुलाई, 1946 के एक दस्तावेज में निर्धारित शर्तों पर सेवा में बने रहने का विकल्प दिया। अपीलार्थी ने उन शर्तों को स्वीकार कर लिया और उस दस्तावेज़ में उल्लिखित शर्तों पर सेवा जारी रखी। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 241 (2,) 247 और 266 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गवर्नर-जनरल ने रेलवे सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा) नियम, 1949 नामक कुछ नियमों को लागू किया, जिन्हें इसके बाद सुरक्षा नियम के रूप में संदर्भित किया गया और वे 14 मई, 1949 को लागू हुए।

इस स्तर पर सुरक्षा नियमों को निर्धारित करना सुविधाजनक होगा, जहां तक वे इन अपीलों के उद्देश्य के लिए सामग्री हैं, क्योंकि इन नियमों की वैधता ही हमारे द्वारा निर्धारित करने का मुख्य बिंदु है। नियम 3, 4, 5 और 7 इस प्रकार हैंः-

> "3. रेलवे सेवा का कोई सदस्य, जो सक्षम प्राधिकारी की राय में विध्वंसक गतिविधियों में लगा हुआ है या जिसके बारे में यथोचित संदेह है, या अपनी विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा करने के लिए इस तरह से विध्वंसक गतिविधियों में दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है, उसे अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त किया जा सकता है, या अपनी सेवा समझौते की शर्तों के अनुसार इस तरह के नोटिस के बदले में उचित सूचना या वेतन दिए जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी सेवा समाप्त की जा सकती हैः
>
> बशर्ते कि रेलवे सेवा का कोई सदस्य इतना सेवानिवृत्त नहीं होगा या उसकी सेवा को इस तरह से समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान न हो कि सार्वजनिक सेवा में

उसका बने रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिकूल है, और जब तक कि सक्षम प्राधिकारी किसी विभाग का प्रमुख न हो, गवर्नर-जनरल की पूर्व मंजूरी न हो।

4. जहां सक्षम प्राधिकारी की राय में, यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि रेलवे सेवा का कोई सदस्य नियम 3 के तहत सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा समाप्त करने के लिए उत्तरदायी है, तो वह

(ए) लिखित आदेश द्वारा, रेलवे सेवा के उक्त सदस्य से ऐसी छुट्टी पर आगे बढ़ने की अपेक्षा करेगा जो उसे स्वीकार्य हो और ऐसी तारीख से जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए;

(बी) लिखित सूचना द्वारा उसे नियम 3 के तहत उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में सूचित करें;

(सी) उसे उस कार्रवाई के खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर दें; और

(डी) नियम 3 के तहत अंतिम आदेश पारित करने से पहले, इस संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी भी अभ्यावेदन को ध्यान में रखें।

5. राज्य रेलवे प्रतिष्ठान संहिता, खंड । के अध्याय XVII में नियमों में निहित कुछ भी इन नियमों के तहत की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर या उसके संबंध में लागू नहीं होगा।

7. कोई भी व्यक्ति जो अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है या जिसकी सेवा नियम 3 के तहत समाप्त की गई है, वह ऐसे मुआवजे, पेंशन, उपदान और/या भविष्य निधि लाभों का हकदार होगा जो ऐसी सेवानिवृत्ति या सेवा की समाप्ति की तारीख को उसकी सेवा या पद पर लागू नियमों के तहत उसे स्वीकार्य होता, अगर उसे बिना किसी वैकल्पिक उपयुक्त रोजगार के अपने पद के उन्मूलन के कारण सेवा से छुट्टी दे दी गई होती।"

6 जुलाई, 1950 को बंगाल नागपुर रेलवे के महाप्रबंधक ने अपीलार्थी को सुरक्षा नियमों की धारा 3 के तहत एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि उसमें पढ़े गए तथ्यों को देखते हुए यह मानने का कारण था कि अपीलार्थी विध्वंसक गतिविधियों में शामिल था और उसे कारण दिखाने के लिए कहा कि उसकी सेवाओं को क्यों समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। उस तारीख से उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था। 29 जुलाई, 1950 को अपीलार्थी ने 6 जुलाई, 1950 के नोटिस में निहित आरोपों से इनकार करते हुए अपना स्पष्टीकरण भेजा। इसके बाद मामला सलाहकारों की समिति को भेजा गया, जिसने 8 सितंबर, 1950 को जांच की और अपीलार्थी को सुनने के बाद पाया कि नोटिस में उनके खिलाफ उल्लिखित आरोप सही थे। इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, महाप्रबंधक ने 3 अप्रैल, 1951 को अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त कर दिया, उन्हें नोटिस के बजाय एक महीने का वेतन दिया।

इस बीच, 3 फरवरी, 1951 को अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर की थी, जिसमें से 1956 की सिविल अपील संख्या 46 नागपुर उच्च न्यायालय में 6 जुलाई, 1950 के नोटिस की वैधता और उसके बाद निलंबन के आदेश को चुनौती देती है। 3 अप्रैल, 1951 का बर्खास्तगी का आदेश, इस याचिका के लंबित रहने के दौरान पारित किया गया था, अपीलार्थी ने अपनी याचिका में एक प्रार्थना जोड़कर संशोधन किया था कि वह

आदेश भी खराब था। याचिका के समर्थन में जिन आधारों का आग्रह किया गया था, वे थे कि जिन सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई की गई थी, वे कला का उल्लंघन थे। संविधान के 14,19 (1) (सी) और 311 और इसके परिणामस्वरूप, इससे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेश अमान्य थे। उत्तरदाताओं ने इस आधार पर आवेदन का विरोध किया कि विचाराधीन नियम वैध थे, और इसके तहत पारित आदेश खुले नहीं थे। याचिका पर अन्य लोगों के साथ सुनवाई की गई, जिसमें वही सवाल उठाए गए थे और 16 नवंबर, 1951 के अपने फैसले में विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि यह तय करना अनावश्यक था कि क्या सुरक्षा नियम अमान्य थे, क्योंकि यह मानते हुए कि वे थे, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने वाले आदेशों को रेलवे प्रतिष्ठान संहिता की धारा 148 के तहत कायम रखा जा सकता है। नियम 148 के उप-नियम (3) और (4) जो इस बिंदु पर लागू होते हैं, वे इस प्रकार हैंः

इस बीच, 3 फरवरी, 1951 को अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर की थी, जिसमें से 1956 की सिविल अपील संख्या 46 नागपुर उच्च न्यायालय में 6 जुलाई, 1950 के नोटिस की वैधता और उसके बाद निलंबन के आदेश को चुनौती देती है। 3 अप्रैल, 1951 का बर्खास्तगी का आदेश, इस याचिका के लंबित रहने के दौरान पारित किया गया था, अपीलार्थी ने अपनी याचिका में एक प्रार्थना जोड़कर संशोधन किया था कि वह आदेश भी खराब था। याचिका के समर्थन में जिन आधारों का आग्रह किया गया था, वे थे कि जिन सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई की गई थी, वे संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (सी) और 311 का उल्लंघन थे और इसके परिणामस्वरूप, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेश अमान्य थे। प्रत्यर्थियों ने इस आधार पर आवेदन का विरोध किया कि विचाराधीन नियम वैध थे, और इसके तहत पारित आदेश हमले के लिए खुले नहीं थे। याचिका पर अन्य लोगों के साथ सुनवाई की गई, जिसमें वही सवाल उठाए गए और 16 नवंबर, 1951 के अपने फैसले में विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि यह तय

करना अनावश्यक था कि क्या सुरक्षा नियम अमान्य थे, क्योंकि यह मानते हुए कि वे थे, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने वाले आदेशों को रेलवे प्रतिष्ठान संहिता की धारा 148 के तहत कायम रखा जा सकता है। आर. 148 के उप-नियम (3) और (4) जो इस बिंदु पर लागू होते हैं, वे इस प्रकार हैं:

> "3) अन्य (गैर-पेंशन योग्य) रेलवे कर्मचारियों की सेवा नीचे दी गई अवधि के लिए दोनों तरफ से नोटिस पर समाप्त होने के लिए उत्तरदायी होगी। हालाँकि सेवा समझौतों के प्रावधानों के तहत संक्षिप्त बर्खास्तगी या निर्वहन, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति और मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण सेवा की समाप्ति के मामलों में इस तरह की सूचना की आवश्यकता नहीं है।
>
> 4) इस नियम में निर्धारित नोटिस के बदले में, रेलवे प्रशासन की ओर से किसी रेलवे कर्मचारी को नोटिस की अवधि के लिए वेतन देकर उसकी सेवा समाप्त करने की अनुमति होगी।"

विद्वान न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी उप-नियम (3) के भीतर गैर-पेंशन योग्य रेलवे कर्मचारी थे, कि उन्हें उप-नियम (4) के तहत नोटिस के बजाय एक महीने का वेतन दिया गया था, और तदनुसार, विवादित आदेश नियम 148, उप-नियम (3) के तहत उत्तरदाताओं की शक्तियों के अंतर्गत थे। परिणामस्वरूप, याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और इन आदेशों के खिलाफ वर्तमान अपीलों को संविधान के अनुच्छेद 132 (1) और अनुच्छेद 133 (1) (सी) के तहत एक प्रमाण पत्र पर प्राथमिकता दी गई है।

अपीलार्थी शिकायत करते हैं कि जिस आधार पर निर्णय की कार्यवाही प्रत्यर्थियों द्वारा अपने अभिवचनों में सामने नहीं रखी गई थी और उन्हें इसे लेने की अनुमति नहीं

दी जानी चाहिए थी; और यह कि वास्तव में मुद्दे वाले बिंदुओं पर, यह माना जाना चाहिए था कि सुरक्षा नियम संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (सी) और 311 के प्रतिकूल थे, और इसलिए, अमान्य थे। वे आगे तर्क देते हैं कि भले ही सुरक्षा नियम वैध थे, सेवाओं को समाप्त करने के आदेश उनके द्वारा उचित नहीं थे, और इसके अलावा, वे आदेश इस कारण से खराब थे कि वे सक्षम अधिकारियों द्वारा नहीं किए गए थे। अपीलकर्ताओं ने यह तर्क भी देना चाहा कि अधिकारियों द्वारा की गई जांच दोषपूर्ण थी, और नियमों द्वारा प्रदान की गई कोई उचित सुनवाई नहीं थी, लेकिन हमने उस बिंदु पर उन्हें सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह उनकी याचिकाओं में नहीं उठाया गया था।

इन अपीलों में निर्णय के लिए बिंदु हैं:

(I) क्या अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त करने के आदेशों को रेलवे प्रतिष्ठान संहिता की धारा 148 के तहत बरकरार रखा जा सकता है;

(II) क्या सुरक्षा नियम उल्लंघन के रूप में खराब हैं (ए) अनुच्छेद 14, (बी) अनुच्छेद 19 (1) (सी) और (सी) संविधान का अनुच्छेद 311;

(III) क्या विवादित आदेश सुरक्षा नियमों के अनुसार भी मान्य नहीं हैं; और (IV) क्या वे आदेश सक्षम अधिकारियों द्वारा पारित नहीं किए गए थे।

(I) पहले प्रश्न पर, अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने केवल सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई करने का इरादा किया था। 6 जुलाई, 1950 का नोटिस उन नियमों के नियम 3 के तहत जारी किया गया था। इसमें निर्धारित प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन करते हुए ही आरोपों के जवाब में अपीलार्थियों का स्पष्टीकरण लिया गया और मामलों को जांच के लिए सलाहकारों की समिति को भेजा

गया। और सबसे बढ़कर, अपीलार्थियों की सेवाओं को समाप्त करने वाले आदेशों के संदर्भ में कहा गया है कि वे नियमों के नियम 3 के तहत किए गए थे, उदाहरण के लिए, 1956 की सिविल अपील संख्या 46 में अपीलार्थी को दी गई 3 अप्रैल, 1951 की सूचना, जो इस प्रकार हैः

> "मैंने इस कार्यालय पत्र संख्या कॉन/टी/21/एम. पी./82 दिनांक 6-7-1950 के जवाब में आपके अभ्यावेदन पर विचार किया है और यह राय दी है कि आप अपनी विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा करने के लिए विध्वंसक गतिविधियों में दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं और मैं संतुष्ट हूं कि सार्वजनिक सेवा में आपका प्रतिधारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिकूल है। मैंने राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ निर्णय लिया है कि रेलवे सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा) नियम, 1949 के नियम 3 के तहत आपकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।"

यह जोड़ा जाना चाहिए कि जबकि अपीलकर्ताओं ने अपनी याचिकाओं में कहा कि उनके खिलाफ सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई की गई थी, और वे नियम अधिकार से बाहर थे, उत्तरदाताओं ने यह दलील नहीं दी कि कार्रवाई रेलवे प्रतिष्ठान संहिता के नियम 148 के तहत की गई थी। उन्होंने केवल यह तर्क दिया कि सुरक्षा नियम वैध थे। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थियों के लिए श्री उमरीगर की यह आलोचना कि अपील के तहत निर्णय एक ऐसे आधार पर आगे बढ़ता है जो न केवल अधिकारियों के विचार में था, जब उन्होंने विचाराधीन आदेश पारित किए थे, बल्कि अदालत में दलीलों में भी नहीं उठाया गया था।

यह तर्क दिया जाता है कि जब कोई प्राधिकरण कोई आदेश पारित करता है जो उसकी क्षमता के भीतर होता है, तो वह केवल इसलिए विफल नहीं हो सकता है क्योंकि वह एक गलत प्रावधान के तहत बनाया गया है, यदि इसे किसी अन्य नियम के तहत उसकी शक्तियों के भीतर दिखाया जा सकता है, और यह कि किसी आदेश की वैधता का निर्णय उसके सार पर विचार करने पर किया जाना चाहिए, न कि उसके रूप पर। इस प्रस्ताव पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्तर पर उत्तरदाताओं का यह तर्क नहीं रहा है कि विचाराधीन आदेश वास्तव में रेलवे प्रतिष्ठान संहिता के नियम, 148 (3) के तहत दिए गए थे और कार्यवाही में सुरक्षा नियमों के नियम 3 के संदर्भ को गलती के कारण नजरअंदाज किया जा सकता है। न्यायालय में विद्वान न्यायाधीशों ने अपने निष्कर्ष को इस आधार पर रखा कि 5 जुलाई, 1946 के सेवा समझौते के खंड (10) में यह प्रावधान किया गया है कि 1 अक्टूबर, 1946 को या उसके बाद नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होने वाले रेलवे नियम ऐसे अन्य मामलों में से एक हैं, नियम 148 (3) ऐसे नियमों में से एक था और अपीलकर्ता जो गैर-पेंशन योग्य रेलवे कर्मचारी थे, वे उस नियम द्वारा शासित थे और उनके अनुसार निर्वहन के लिए उत्तरदायी थे। लेकिन यह तर्क इस बात की अनदेखी करता है कि सेवा समझौते के खंड (10) के तहत, सुरक्षा नियम रेलवे प्रतिष्ठान संहिता के नियमों के समान ही हैं और नियम 148 के साथ समान रूप से सेवा की शर्तों का गठन करते हैं जिन पर अपीलकर्ताओं ने रोजगार किया था, और ऐसे ठोस कारण होने चाहिए कि नियम 3 के तहत स्पष्ट रूप से पारित आदेशों को उस नियम के तहत पारित नहीं किया गया था। हमसे पहले, उत्तरदाताओं द्वारा एक अलग रुख अपनाया गया था। उन्होंने इस बात पर विवाद नहीं किया कि कार्रवाई वास्तव में सुरक्षा नियमों के नियम 3 के तहत की गई थी, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि नियम 3 के तहत सेवा को समाप्त करने की शक्ति, नियम 148 द्वारा प्रदत्त निर्वहन की शक्ति से कुछ अलग और स्वतंत्र नहीं थी, और यह

कि नियम 3 के तहत पारित आदेश, अपनी शर्तों पर, नियम 148 (3) के तहत बनाया गया था। इस तर्क का आधार नियम 3 में प्रावधान है कि सेवा समझौते के अनुसार, उचित सूचना देने या इस तरह के नोटिस के बदले भुगतान करने के बाद सेवा को समाप्त किया जा सकता है।

हम उत्तरदाताओं के तर्क को स्वीकार करने में काफी कठिनाई पाते हैं। सुरक्षा नियम कर्मचारियों के एक विशेष वर्ग पर लागू होते हैं, जो विध्वंसक गतिविधियों में लगे हुए हैं या शामिल होने की संभावना रखते हैं, और उन निर्देशों के संयोजन के साथ जो जारी किए गए थे जब उन्हें घोषित किया गया था, वे एक स्व-निहित कोड बनाते हैं जो एक विशेष और विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है जिसका पालन किया जाना है, जब उसके तहत कार्रवाई की जानी है। हम अपीलार्थियों के इस तर्क में काफी बल देखते हैं कि नियम 3 में सेवा समझौते का उल्लेख केवल दिए जाने वाले नोटिस की प्रकृति का संदर्भ देता है। यदि उत्तरदाता सुरक्षा नियमों पर जो व्याख्या करना चाहते हैं वह सही है, तो यह देखना मुश्किल है कि वे किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। उत्तरदाताओं के लिए श्री गणपति अय्यर का तर्क है कि उनका उद्देश्य उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना है जिन पर विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया जा सकता है। यदि यह उनका उद्देश्य है, तो यदि उसके तहत कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तो आदेश को गलत माना जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी को दिए जाने वाले संरक्षण से इनकार कर दिया गया है, और नियम 148 को ऐसे आदेश को वैधता देने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

वास्तव में, यह संबंधम बनाम महाप्रबंधक, एस.आई. (1) और प्रसादी बनाम कार्य प्रबंधक, लिल्लोह (1) में किया गया है और यह भी श्री गणपति अय्यर द्वारा स्वीकार किया गया है। यदि तब सुरक्षा नियमों के तहत सेवा को समाप्त करने की शक्ति

नियम 148 के तहत निर्वहन करने की शक्ति से अलग है, जब निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तो यह बराबर होना चाहिए, इसलिए जब यहाँ इसका पालन किया गया है, क्योंकि नियम उनके अनुसार नहीं बदल सकता है जैसा कि उनका पालन किया जाता है या नहीं। इसका मतलब है कि सुरक्षा नियमों का अपना एक स्वतंत्र संचालन है, जो नियम 148 से बिल्कुल अलग है। हालाँकि, हम इस प्रश्न पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि श्री गणपति अय्यर इस बात के इच्छुक हैं कि विचाराधीन आदेशों की वैधता इस आधार पर निर्धारित की जा सकती है कि वे नियम 148 के संदर्भ के बिना सुरक्षा नियमों के नियम 3 के तहत पारित किए गए थे। इससे यह तय करना आवश्यक हो जाता है कि क्या सुरक्षा नियम असंवैधानिक हैं, जैसा कि अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है।

(2 क) सुरक्षा नियमों की वैधता के खिलाफ पहला आधार यह है कि वे अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल हैं। यह कहा जाता है कि इन नियमों ने एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है जहां विध्वंसक गतिविधियों के संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, और जब किसी कर्मचारी की सेवाओं को इन नियमों के तहत समाप्त कर दिया जाता है, तो इसका परिणाम उसे अविश्वसनीय और कुख्यात के रूप में मुहर लगाना होता है, और इस प्रकार भेदभाव होता है, जैसा कि अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित होता है। यह स्वीकार किया जाता है कि यदि इन नियमों के तहत जिन व्यक्तियों के साथ व्यवहार किया जाता है, वे एक अलग वर्ग बनाते हैं, जिसमें एक बोधगम्य अंतर होता है जो नियमों के उद्देश्यों के साथ उचित संबंध रखता है, तो अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन यह तर्क दिया जाता है कि वर्गीकरण का आधार बनने वाली "विध्वंसक गतिविधियाँ" अभिव्यक्ति अस्पष्ट और परिभाषित नहीं है क्योंकि इसमें वैध गतिविधियों को भी शामिल किया जा सकता है, और इस तरह के वर्गीकरण को उचित नहीं कहा जा सकता है। 1956 की सिविल अपील संख्या 46 में अपीलार्थी पर

लगाए गए उन आरोपों का संदर्भ दिया गया था जो यह दर्शाते हैं कि कैसे वैध संबंधों को भी विवादित नियमों के तहत लाया जा सकता है। जहां तक इसकी सामग्री की बात है, यह सूचना इस प्रकार हैः

जबकि महाप्रबंधक की राय है कि आपको बी.एन. रेलवे श्रमिक संघ (कम्युनिस्ट प्रायोजित) का सदस्य और कार्यालय सचिव होने का संदेह है और आप ओम प्रकाश मेहता, बी. एन. मुखर्जी, आर. एल. रेड्डी आदि जैसे कम्युनिस्टों के साथ इस तरह से जुड़े हुए थे कि राज्य के प्रति आपकी विश्वसनीयता और वफादारी के बारे में संदेह पैदा हो, भले ही आप एक सरकारी कर्मचारी हों, आपने कम्युनिस्टों की निजी बैठकों में भाग लिया हो, लेकिन नवंबर 1948 से जनवरी 1949 तक सामान्य हड़ताल के लिए रेलवे कर्मचारियों के बीच आंदोलन चलाया, जिससे संचार और आवश्यक आपूर्ति की आवाजाही बाधित हो गई और इस तरह देश में अव्यवस्था और भ्रम पैदा हुआ और इसके परिणामस्वरूप, आप उक्त नियमों के नियम 3 के तहत अपनी सेवाओं को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं।

यह तर्क दिया जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होना या ट्रेड यूनियन गतिविधियों में शामिल होना गैरकानूनी नहीं है, और यदि यह नियमों के तहत कार्रवाई का आधार बन सकता है, तो वर्गीकरण को अनुचित माना जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "त्वरित सुनवाई" सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामान्य न्यायालयों से अलग प्रक्रिया के तहत विशेष अदालतों द्वारा मुकदमे के लिए मामलों का चयन करने के लिए कार्यपालिका को प्रदत्त शक्ति को अनुच्छेद 14 के तहत एक वैध वर्गीकरण के रूप में बरकरार नहीं रखा जा सकता था, और अनंतनारायणन बनाम दक्षिणी रेलवे (1) में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर,

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियम 3 में "विध्वंसक गतिविधियों" शब्दों में निश्चितता का अभाव है।

अब, यह निर्धारित करने के लिए लागू सिद्धांत कि क्या अनुच्छेद 14 के उद्देश्यों के लिए एक उचित और वैध वर्गीकरण किया गया है, इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में विचार का विषय रहा है, और उन्हें हाल ही में बुधन चौधरी और अन्य बनाम बिहार राज्य (1) में फिर से कहा गया था, और उन्हें दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन अपीलों में निर्णय लेने के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि क्या विध्वंसक गतिविधियों के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण एक वैध वर्गीकरण की नींव होने के लिए बहुत अस्पष्ट है। श्री उमरीगर जोर देकर कहते हैं कि यह है, लेकिन उनका विस्तृत तर्क इससे अधिक कुछ नहीं है कि अभिव्यक्ति और अन्य "विध्वंसक गतिविधियों" को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लिया जा सकता है, और इसलिए इसकी सामग्री व्यापक है। यह हो सकता है कि उस अभिव्यक्ति का अर्थ व्यापक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह अस्पष्ट या अनिश्चित है। लेकिन स्थिति जो भी हो अगर "विध्वंसक गतिविधियाँ" शब्द अपने आप में खड़े थे, तो वे निश्चित होने के लिए सुरक्षा नियमों में पर्याप्त रूप से योग्य हैं। उन नियमों का, उनके उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना है जैसा कि संक्षिप्त शीर्षक में पढ़ा गया है। नियम 3 में इस बात पर फिर से जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि रेलवे सेवा के किसी सदस्य को तब तक सेवानिवृत्त नहीं किया जाना चाहिए या उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अधिकारी इस बात से संतुष्ट न हों कि सार्वजनिक सेवा में उसका बने रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है। हमारे निर्णय में, राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में "विध्वंसक गतिविधियाँ" शब्द एक वैध वर्गीकरण को बनाए रखने के लिए उनके महत्व में पर्याप्त रूप से सटीक हैं। हम अनंतनारायणन बनाम दक्षिणी रेलवे (उपरोक्त)

223 में व्यक्त राय से सहमत नहीं हैं कि नियम 3 की भाषा अनिश्चित है, भले ही इसे "राष्ट्रीय सुरक्षा" शब्दों के साथ पढ़ा जाए।

हम 6 जुलाई, 1950 के नोटिस में 1956 की सिविल अपील संख्या 46 में अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर अपीलार्थियों के तर्क से भी सहमत होने में असमर्थ हैं, कि "विध्वंसक गतिविधियाँ" अभिव्यक्ति वैध गतिविधियों में भी लेने के लिए पर्याप्त है, और इसलिए इसे अनुच्छेद 14 के तहत वर्गीकरण के उद्देश्यों के लिए अनुचित माना जाना चाहिए। यह सच है कि नोटिस अपीलार्थी के कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होने और ट्रेड यूनियन में उसकी गतिविधियों को संदर्भित करता है। यह भी सच है कि कम्युनिस्ट या ट्रेड यूनियनवादी होना गैरकानूनी नहीं है। लेकिन यह किसी कम्युनिस्ट या ट्रेड यूनियनवादी का आवश्यक गुण नहीं है कि वह विध्वंसक गतिविधियों में शामिल हो, और जब नियमों के तहत अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो यह इसलिए नहीं था कि वह कम्युनिस्ट या ट्रेड यूनियनवादी था, बल्कि इसलिए कि वह विध्वंसक गतिविधियों में लगा हुआ था। हम मानते हैं कि सुरक्षा नियम अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल होने के कारण अवैध नहीं हैं।

(2 ख) इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि विवादित आदेश अनुच्छेद 19 (।) (c) के उल्लंघन में हैं, और इसलिए अमान्य हैं। तर्क यह है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की गई है, क्योंकि वे कम्युनिस्टों और ट्रेड यूनियनवादियों को घेरते हैं, और नियम 3 के तहत उनकी सेवाओं को समाप्त करने के आदेश, वास्तव में, उन्हें संघ बनाने की स्वतंत्रता से वंचित करने के बराबर हैं, जिसकी गारंटी अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत दी गई है। हम पहले ही देख चुके हैं कि यह आरोपों का वास्तविक दायरा नहीं है। लेकिन इसके अलावा, हम यह नहीं देखते हैं कि अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत अपीलार्थियों के किसी भी अधिकार का उल्लंघन कैसे

किया गया है। आदेश उन्हें कम्युनिस्ट या ट्रेड यूनियनवादी बने रहने से नहीं रोकते हैं। उस ओर से उनके अधिकार विवादित आदेशों के बाद ठीक वैसे ही रहते हैं जैसे वे पहले थे। अपीलार्थियों की वास्तविक शिकायत यह है कि उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है; लेकिन इसमें अनुच्छेद 311 के अलावा, उनके किसी भी संवैधानिक अधिकार का कोई उल्लंघन शामिल नहीं है। अपीलार्थियों को इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत संघ बनाने का मौलिक अधिकार है, लेकिन उन्हें राज्य द्वारा रोजगार में बने रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, और जब उनकी सेवाओं को राज्य द्वारा समाप्त कर दिया जाता है तो वे अपने किसी भी संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकते हैं, जब अनुच्छेद 311 के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अपीलार्थियों के इस तर्क को भी खारिज किया जाना चाहिए।

(2 सी) तब यह तर्क दिया जाता है कि आरोपों की सुनवाई के लिए सुरक्षा नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुच्छेद 311 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, और इसके परिणामस्वरूप वे अमान्य हैं। लेकिन अनुच्छेद 311 केवल तभी लागू होता है जब बर्खास्तगी या हटाने का आदेश होता है, और सवाल यह है कि क्या नियम 3 के तहत कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को उन्हें बर्खास्त करने या हटाने का आदेश कहा जा सकता है। अब, इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में कहा है कि यह किसी कर्मचारी की सेवाओं की प्रत्येक समाप्ति नहीं है जो अनुच्छेद 311 के संचालन के अंतर्गत आती है, और यह केवल तभी है जब आदेश दंड के रूप में है कि यह उस अनुच्छेद के तहत बर्खास्तगी या निष्कासन का एक है। सतीश चंद्र आनंद बनाम भारत संघ (1), श्याम लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और भारत संघ (1), बॉम्बे राज्य बनाम सौभाग्यचंद एम. दोशी (1), और परशोतम लाल ढींगरा बनाम भारत संघ (1)। यह सवाल कि अनुच्छेद 311 के उद्देश्यों के लिए सजा क्या होगी, परशोतम लाल ढींगरा के मामले (ऊपर) में भी पूरी तरह से विचार किया गया था। इसमें यह

अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि किसी व्यक्ति को सेवा नियमों के तहत या किसी विशेष समझौते के तहत पद पर बने रहने का अधिकार है, तो उसकी सेवाओं की समय से पहले समाप्ति एक दंड होगा। और, इसी तरह, यदि आदेश के परिणामस्वरूप पहले से अर्जित और उपार्जित लाभों का नुकसान होगा, तो वह भी सजा होगी। वर्तमान मामले में, रोजगार की शर्तों में उचित सूचना पर सेवाओं को समाप्त करने का प्रावधान है, और इसलिए, समय से पहले समाप्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सुरक्षा नियमों का नियम 7 कर्मचारी के पेंशन, उपदान और इसी तरह के सभी लाभों के अधिकारों को संरक्षित करता है, जिसके वे नियमों के तहत हकदार होंगे। इस प्रकार, पहले से प्राप्त लाभों को जब्त नहीं किया जाता है। अपीलार्थियों के लिए यह कहा गया था कि एक व्यक्ति जिसे नियमों के तहत छुट्टी दे दी गई थी, वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था, और वह सजा थी। लेकिन अपीलार्थी उस अक्षमता को लागू करने वाले किसी भी नियम की ओर इशारा करने में असमर्थ हैं। सुरक्षा नियमों के नियम 3 के तहत सेवाओं को समाप्त करने का आदेश नियम 148 के तहत निर्वहन के आदेश के समान है, और यह न तो बर्खास्तगी का है और न ही अनुच्छेद 311 के अर्थ के भीतर हटाने का है। इस विवाद को भी खारिज किया जाना चाहिए।

(3) इसके बाद श्री उमरीगर द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि 6 जुलाई, 1950 के नोटिस में 1956 की सिविल अपील संख्या 46 में अपीलार्थी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, उनमें उन घटनाओं का संदर्भ है जो सुरक्षा नियमों के लागू होने से पहले हुई थीं, जो 14 मई, 1949 को थे और उस पर आधारित अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश नियमों को पूर्वव्यापी संचालन देने के रूप में खराब है, और यह कि वे इसकी शर्तों द्वारा वारंट नहीं हैं। अब, नियमों में यह प्रावधान है कि उनके तहत कार्रवाई की जा सकती है, यदि कर्मचारी विध्वंसक गतिविधियों में लगा हुआ है या यथोचित रूप से संदेह है। जहाँ किसी प्राधिकारी को यह राय बनानी होती है कि किसी कर्मचारी के

विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना है. यह केवल कर्मचारी के आचरण के क्रम से निष्कर्ष के रूप में हो सकता है, और उसके पूर्वजों को इसके लिए सर्वोत्तम सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए। नियम स्पष्ट रूप से संभावित हैं कि इसके तहत उन विध्वंसक गतिविधियों के संबंध में कार्रवाई की जानी है जो या तो अब मौजूद हैं या भविष्य में शामिल होने की संभावना है, अर्थात, जो अनिवार्य हैं या स्थिति में हैं कि बाद के मामले में कार्रवाई करने के लिए सामग्री नियमों के अधिनियमन से पहले कर्मचारियों के आचरण से ली गई है, दस्तावेज़ उनके संचालन को पूर्वव्यापी नहीं बनाते हैं। द क्वीन बनाम सेंट मैरी, व्हाइटक्लूपेल (1) और द क्वीन बनाम क्राइस्टचर्च (1) में लॉर्ड डेनमैन सी. जे. की टिप्पणियों को देखें। इस तर्क को भी खारिज किया जाना चाहिए।

(IV) अंत में, यह तर्क दिया गया कि विवादित आदेश सुरक्षा नियमों के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा पारित नहीं किए गए थे और इसलिए वे अमान्य थे। यह तर्क इस तथ्य पर आधारित है कि नियम 3 के तहत आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी वर्तमान अपीलार्थी महाप्रबंधक के संबंध में है, और यह कि विवादित आदेश वास्तव में उप प्रबंधक द्वारा उन्हें सूचित किए गए थे। लेकिन यह एक तथ्य के रूप में पाया गया है कि आदेश वास्तव में महाप्रबंधक द्वारा पारित किए गए थे, और उस निष्कर्ष को स्वीकार किया जाना चाहिए। नतीजतन, अपील विफल हो जाती हैं और लागत के साथ खारिज कर दी जाती हैं। जिन अपीलार्थियों को अपील दायर करने की अनुमति दी गई थी, वे सरकार को देय अदालती शुल्क का भी भुगतान करेंगे।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सपना राजपुरोहित द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।